REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 10 | JULY - 2018

डिजीटल इण्डिया का मध्यप्रदेश शासन में प्रयोग

डॉ. दीपक कुमार मोदी
अतिथि शिक्षक , राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग ,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

Abstract (सारांश) –

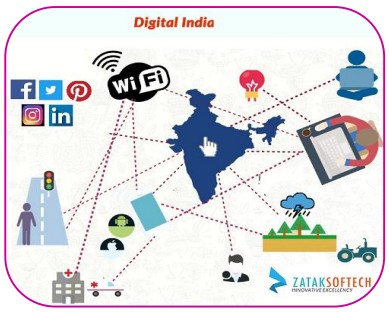

भारतीय लोक प्रशासन की यह नूतन दिशा है कि वर्तमान में विश्व में होने वाले नवाचारों को भारत में भी प्रयोग किया जा रहा है। भारत डिजिटल लॉकर, ई–शिक्षा, ई–स्वास्थ्य, ई–हस्ताक्षर, ई–आधार और केसलेस इंडिया के माध्यम से भारत को सुशासन की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है। नौकरशाही और लालफीताशाही के बंधनों से मुक्ति की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया के पीछे मूल दृष्टि है देश के हर–नागरिक के लिए डिजिटल आधारभूत ढाँचे तक पहुँच सुनिश्चित करना तथा नागरिकों को विविधि प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराना। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकारी सेवाओं तक पहुँच सके यही डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है।

Keywards (मुख्य बिन्दु) – सूचना प्रौद्योगिकी, सुशासन, डिजीटल, ई–प्रशासन, ई–क्रांति, सामाजिक सरोकार

Introduction -(प्रस्तावना) –

वर्तमान युग में जन आवश्यकताओं की बढ़ती मांग का सामना करने के लिए विश्व के सभी देशों में सूचना प्रौधोगिकी को विकसित कर प्रशासनिक योग्यता में वृद्धि का प्रयास हो रहा है। इसके लिए प्रशासनिक संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं में सुधार की चुनौती सामने आयी है। विश्व के अधिकांश विकासशील देशों में समपार्श्वीय लक्षणों के साथ नौकरशाही के विधिक तार्किक प्रारूप को अपनाया है।

''ई'' उपसर्ग के साथ प्रशासन अपनी क्रियात्मकता को इलेक्ट्रॉनिक्स या आंगुलिक प्रकृति में ढालने का प्रयत्न कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचनाओं एवं संचार प्रौधोगिकी का सहारा लेकर सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था एवं सेवा वितरण के ऐसे पूरक एवं वैकल्पिक प्रारुप को विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिसके न सिर्फ सरकार की सामर्थ्य शक्ति में गुणात्मक वृद्धि हो बल्कि लोक तथा निजी क्षेत्र के बीच अंतक्रियात्मक संबंधो को नए सिरे से परिभाषित किया जा सके। ''ई'' के प्रथम अर्थ ''दक्षता'' की गुणवत्ता को समाहित करते हुए सत्कार उत्पादन लागत की न्यूनता के, संभव बनाने का प्रयत्न कर रही है। सूचना प्रौधोगिकी का सहारा लेकर सत्कार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नौकरशाही प्रक्रियाओं के रूढ़ीवादिता को कम कर क्रियात्मकता को दक्षता में वृद्धि करे एवं बेहतर संगठित तथा आर्थिक दृष्टिकोण की साथ सेवा वितरण के कर्त्तव्य का निर्वहन कर सके।[1]

अधिशासन की अवधारणा में अधिकाधिक तथ्य निहित है जो समाज विकास अभिमुखन से संबधित होते है। मूल रुप से इसे सरकार के विकल्प स्वरुप में देखा गया है। और माना गया है कि समाज पर नियंत्रण या उनके प्रति अभिमुखन श्रेणी बद्ध पदानुक्रम की शक्ति नही हो सकता। विकास वृद्धि में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं

की भूमिका रहती है जो क्रम वृद्ध स्वरूप में जाल तंत्रा के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति करते है। सरकार की सक्रिय भूमिका और उत्तम संस्थानों का निर्माण महत्वपूर्ण माना गया है।[2]

वर्तमान समय में अच्छा प्रशासन देने के लिए तकनीक का उपयोग करना जरूरी है। जनता के प्रशासन से जुड़ने का सशक्त डिजिटल माध्यम है। इससे कम समय में जनता सरकार से जुड़ेगी तथा सुझाव और समस्याओं की जानकारी दे सकेगी। ई– गर्वेनेंस से भ्रष्टाचार पर रोक के साथ लोगों को त्वरित सेवाएं मिलेगी।

अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक महत्त्वपूर्ण सम्मेलन डिजिटल इंडिया पर केंद्रित होने वाला है। उधर वियतनाम ने डिजिटल इंडिया की तर्ज पर अपने यहाँ भी एक दीर्घकालीन कार्यक्रम शुरु करने

की बात कही है। नोबेल पुरुस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने दावोस में कहा कि अमेरिका को डिजीटल अर्थव्यवस्था की तरफ प्रधानमंत्राी श्री नरेन्द्र मोदी के कदमों का अनुसरण करना चाहिये।

ये घटनाएं और ये टिप्पणियां इस बात की निशानदेही करती है कि पिछले कुछ महीनों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर लोगों को प्रेरित किया है। असल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे अनदेखा करना दुनिया के लिये असंभव है। मिसाल के तौर पर यह तथ्य कि ''आधार'' दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कायय़ाब सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के रूप में सामने आई है। एक अरब से ज्यादा लोगों को पुष्टि–योग्य डिजिटल पहचान प्रदान करना एक ऐसा लक्ष्य था जिसकी कामयाबी में शुरु से ही संदेह किया जा रहा था। लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। और अब जिस तरह हम नकदी रहित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे है, वह विश्व के आर्थिक–प्रशासनिक इतिहास में एक और मिसाल कायम करने जा रहा है।[3]

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्यापकता प्रभाव गहनता और नवीनता में लगातार वृद्धि होना प्रभावित करता है। हालांकि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बहुत सी चुनौतियां और सीमाएं भी है जो भारत जैसे विविधतापूर्ण तथा आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से विकासमान देश के लिये स्वभाविक है। लेकिन इस बात में कतई संदेह नहीं है कि डिजिटल इंडिया ने देश में डिजिटल सोच, डिजिटल नवोन्मेष डिजिटल जागरुकता और डिजिटल महत्वाकांक्षा का माहौल बना दिया है। सरकारी विभागों में नए–नए डिजिटल कार्यक्रम शुरु करने की साफ होड़ दिखाई देती है तो राज्य सरकारें भी किसी से पीछे नहीं हैं।

खैर, सरकारें तो सरकारें है और उनके सामाजिक सरोकार एक अनिवार्यता है। लेकिन जिस बात से खासा संतोष होता है वह यह है कि निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी डिजिटल इंडिया से जुड़कर गौरव का अनुभव कर रही है। वे इस कार्यक्रम की कामयाबी में अपनी तरफ से योगदान देना चाहती है। कुछ उदाहरण काबिले गौर है – माइक्रोसॉफ्ट ने इसी महीने जयपुर में एक कार्यक्रम में दस हजार रुपये से कम कीमत का लैपटॉप जारी किया, इस संकल्प के साथ कि ऐसे लैपटॉप डिजिटल क्रांन्ति को गाँव–गाँव तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस लैपटॉप में विंडोज का अधिकारिक (जेनुइन) संस्करण मौजूद है और तमाम वे सुविधाएं भी है जिनकी जरुरत सामान्य उपभोक्ता को पड़ती है। याद रहे जब भारत में विमुद्रीकरण या नोटबंदी का एलान हुआ तो माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने विश्वास जताया था कि भारत तेजी से डिजिटल भुगतान की तकनीकों को अंगीकार कर लेगा। जी.एस.टी. इसी कड़ी का हिस्सा है।

इस बीच गूगल ने डिजिटल भुगतान और डिजिटल कौशल में योगदान देने के लिए केन्द्र सरकार के सूचना प्रोद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्राालय के साथ मिलकर बड़ी योजना बनाई है। सिस्को ने साइबर सुरक्षा को चाकचौबंद करने के लिए करार किया है। ज्यों–ज्यों डिजिटल इंडिया का दायरा बढ़ेगा साइबर चुनौतियां भी बढ़नी स्वाभाविक है। सैमसंग ने गाँव–गाँव तक डिजिटल स्मार्ट क्लास ले जाने की योजना शुरु की हैं। एचपी ने भारत में सेंटर और एक्सीलेंस की शुरुआत की है। एचपी ने भारत में सेंटर और एक्सीलेंस की शुरुआत की है। भारत की कंपनियां भी बड़े कदम उठा रही है और हजारों स्टार्टअप भी डिजिटल भारत के निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। निजी क्षेत्रा के प्रयासों में कारोबार की भी भूमिका अवश्य होगी लेकिन वह इस बारे में पर्याप्त लचीलापन दिखा रहा है, इसमें संदेह नहीं है।[4]

अहम बात यह है कि निजी क्षेत्रा में डिजिटल बदलाव (डिजिटल ट्रांसफार्मेशन) का दौर चल रहा है वह उन्हें स्पष्ट रूप से लाभान्वित कर रहा है। यह लाभ सिर्फ आर्थिक हो यह जरुरी नहीं। मिसाल के तौर पर हाल ही में एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि डिजिटल बदलाव से उनकी आय के नए स्त्रोत खुले है। चौरासी

प्रतिशत कंपनियों ने कहा है कि इसकी बदौलत वे अपनी प्रतिद्वन्दी कंपनियों से बेहतर स्थिति में आ गई है। सन्तानवे प्रतिशत कंपनियों का मानना है कि उनके ग्राहकों को अब उनकी सेवाएं पहले से ज्यादा अच्छी महसूस हो रही है। पैंतीस प्रतिशत कंपनियां मानती है कि नए अवसरों का लाभ उठाने की उनकी क्षमता में इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं 56 प्रतिशत ने माना है कि नए बदलावों से उनके कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ी है। डिजिटलीकरण का व्यापक दौर हमारे इर्द–गिर्द घटित हो रहा है जिसके पीछे डिजिटल इंडिया की प्रेरणा या प्रभाव है।

डिजिटल इंडिया एक विशाल अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। वह देश को डिजिटलीकृत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का महत्त्वाकांक्षी उपक्रम है। डिजिटल लॉकर ई–शिक्षा, ई–स्वास्थ्य, ई–हस्ताक्षर और राष्ट्रीय छात्रावृत्ति पोर्टल जैसे कार्यक्रमों के साथ इसकी शुरुआत हुई। बहरहाल इस तरह के कार्यक्रम इसके पीछे की व्यापक दृष्टि के कुछ क्रियान्वयन मात्रा है। डिजिटल इंडिया के पीछे मूल दृष्टि है देश के हर–नागरिक के लिए डिजिटल आधारभूत ढांचे तक पहुँच सुनिश्चित करना और इस ढांचे का उद्देश्य होगा एक माध्यम के रूप में नागरिकों तक विविध प्रकार के सेवाएं उपलब्ध कराना। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकारी सेवाओं और प्रशासन तक पहुंच प्राप्त कर सके यह इसका एक अन्य मकसद है और ये दोनों चीजें तब संभव हो सकेंगी जब नागरिकों को एक डिजिटल आधार पर सशक्त बनाया जाये। ये तीनों बातें डिजिटल इंडिया के विजन का हिस्सा है।

इस कार्यक्रम के नौ आधारभूत स्तंभों ब्रॉडबैंड हाइवे, फोन की सुविधा तक सार्वजनिक पहुँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, ई–प्रशासन, ई–क्रांन्ति (सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी) सबके के लिए सूचना इलेक्ट्रानिक्स का विनिर्माण, रोजगार के लिये सूचना प्रोद्योगिकी और अर्लो –हारवेस्ट कार्यक्रम में से सभी में पिछले ढाई–पौने तीन साल के दौरान काफी प्रगति हुई है।

- ढाई लाख गाँवों में फोन संपर्क की सुविधा पहुंच चुकी होगी।
- सभी स्थानों पर फोन संपर्क की सुविधा सुनिश्चित हो जाएगी।
- 2020 तक सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार के क्षेत्र में उपकरणों के आयात पर निर्भरता न्यूनतम हो चुकी होगी।
- चार लाख सार्वजनिक इंटरनेट प्रयोग केन्द्रों की स्थापना हो चुकी होगी।
- ढाई लाख विद्यालयों और सभी विश्वविद्यालयों में वाई–फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो चुकी होगी।
- बड़ी संख्या में नागरिकों के लिये बाइ–फाई हॉटस्पॉट स्थापित हो चुके होगे।
- सूचना प्रोद्योगिकी, दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्रों में 1.7 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर डिजिटल समावेशन के दायरे में लाया जा चुका होगा।
- इतने ही लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जा चुका होगा और कम से कम 8.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया कराया जा चुका होगा। ई–प्रशासन और ई–सेवाओं को सभी सरकारों के स्तर पर व्यापक बनाया जा चुका होगा।
- स्वास्थ्य शिक्षा और बैकिंग जैसी सेवाओं के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में भारत विश्व का अग्रणी देश बन चुका होगा
- सार्वजनिक क्लाउड और इंटरनेट के प्रसार के जरिए नागरिकों को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाया जा चुका होगा।

जिन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, उनमें इलेक्ट्रानिक या डिजिटल भुगतान का क्षेत्र सबसे आगे दिखई देता है आधार के सूत्राधार नंदन निलेकणी ने हाल ही में कहा है कि भारत में तकनीकी प्रणालियां भुगतान प्रक्रियाएं और आधारभूत ढाँचा इतना सुदृढ़ है कि वह डिजिटल भुगतानों के मौजूदा स्तर के चार गुना तक को आसानी से वहन कर सकता है। एक अरब लोगों को डिजिटल माध्यमों से धन के लेन–देन की सुविधा देने में सक्षम ढाँचा पहले ही हमारे पास मौजूद है। हालांकि पश्चिमी देशों में जहाँ डिजिटल अर्थव्यवस्था में कार्ड– आधारित लेन–देन की बहुतायत है वही भारत में अधिकांश डिजिटल लेन–देन मोबाइल

फोन के माध्यम से होने हैं। यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस एक जानदार परियोजना है जिसने बैंकों को आधार नंबर के माध्यम से धन का स्थानांतरण करने की शक्ति दे दी है।[5]

इतना ही नहीं इसका प्रयोग करते हुए मोबाइल नंबर और पिन के माध्यम से भी धन का लेन–देन संभव हो गया है। इतने बड़े–देश के पैमाने पर इस तरह की योजनाओं का सफलतापूर्वक लागू हो जाना किसी चमत्कार की बदौलत घटित हुआ है। नोबेल पुरुस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिर्न्लट्ज ने अगर अमेरिका को भारत से सबक लेने की नसीहत दी है तो उसके पीछे इन कामयाबियों का बड़ा हाथ है।

डिजिटल मध्यप्रदेश –

मध्यप्रदेश में निवेश के प्रति बने अनुकूल वातावरण को ध्यान में रखते हुए आई.टी.संबंधित अधोसंरचना विकास के कार्य लगातार किये जा रहे है। इसके साथ ही आई.टी.आई.टी.एस. एवं एस.डी.एस निवेश प्रोत्साहन नीति– 2016 जारी की गयी है। नीति में निवेशकों के लिए विभिन्न रियायतों का समावेश किया गया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भी प्रदेश तेजी से कार्य कर रहा है।

आई.टी.पार्क की स्थापना –

प्रदेश के महानगर इंदौर के परदेशीपुरा एवं ग्वालियर में आई.टी.पार्क संचालित है। आई.टी. पार्क परदेशीपुरा का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सिंहासा आई.टी. पार्क इन्दौर, बड़बई, आई.टी.पार्क भोपाल एवं पूरवा जबलपुर में आई. टी. पार्क की स्थापना के प्रथमचरण में मूलभूत अधोसरंचना का विकास 75 प्रतिशत पूरा हो गया है। आई.टी. पार्क इंन्दौर में 14 भोपाल में 25 एवं जबलपुर में 4 ईकाई को भूमि आवंटित की गई है। सागर में आई.टी.पार्क की स्थापना की जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक मेनयुफेक्चरिंग क्लस्टर्स –

मध्यप्रदेश का वह पहला राज्य है, जहाँ एक साथ दो भोपाल एवं जबलपुर इलेक्ट्रानिक्स मेनुफेक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की गयी है। दोनो जगह ईएमसी की मूलभूत अधोसरंचना का विकास कार्य प्रगति पर है। भवन निर्माण का काम अंतिम चरण मे है। परियोजना के सुचारू के लिये प्रदेश मे एक पृथक कम्पनी भोपाल इलेक्ट्रानिक्स मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर मे 5 इकाई को भूमि आवंटित की गई है। क्लस्टर के विकास का कार्य प्रगति पर है क्लस्टर्स के क्षेत्रा में 50,000 रोजगार का सृजन होगा

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) -

मध्यप्रदेश में शासकीय कार्यालायों में नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के तहत दैनिक गतिविधियों का सुगमता प्रणाली के तहत दैनिक गतिविधियो का सुगमत तीव्रता एवं परदर्शिता से निष्पादन किए जाने में स्टेड वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) की महत्वपूर्ण भूमिका है प्रदेश मे भारत सरकार के दिशा– निर्देशानुसार में इस नेटवर्क की स्थापना की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के सहयोग एवं इस परियोजना में मध्यप्रदेश में 400 Point of presence (Pop) केन्द्र की स्थापना की की जा रही है। अब तक 380 पॉप केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। और 40 नवीन तहसील में से 20 में Point of present (pop) केन्द्रों की स्थापना की गई। प्रदेश में इस नेटवर्क के माध्यम से 51 विभाग के कार्यालयों में 10 हजार उपयोगकर्त्ता को (SWAN) से कनेक्टिविटी दी गई है। शासकीय उपयोग में नेटवर्क की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क को निर्बाध रूप से संचालित किए जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

स्टेट रेसीडेंट डाटा हब –

प्रदेश के रहवासियों के केन्द्रीकृत डाटा संधारण डेटाबेस के विश्लेषण तथा उससे बेहतर योजना नियोजन के उद्देश्य से प्रदेश मे स्टेट रेसीडेंट डाटा हब (SRDH) की अधोसंरचना की गयी है। विकसित राज्य में कोमल डाटा रिपोजिटरी के लिए आधारभूत अधोसंरचना स्टेट रेसीडेंट डाटा हब (SRDH) के कार्य

पूर्ण हो चुके हैं। प्रदेश के रहवासियों का 31 अगस्त 2016 तक 85 प्रतिशत आधार पंजीयन हो गया है। शत् प्रतिशत पंजीयन को कार्यवाही जारी है।

स्टेट डाटा सेंटर –

मध्यप्रदेश सरकार के सभी विभाग एवं एंजेसियों में उपलब्ध डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रखने एवं आपस में बॉटने की निरतरता 365 दिन एवं 24 घंटे जारी रखने के लिये भोपाल में वर्ष 2013 से स्टेट डेटा सेंटर क्रियाशील है। वर्तमान में सेंटर (SDC) में विभिन्न विभाग की 314 एप्लीकेशन्स चल रही है।

ई– टेण्डरिंग –

शासकीय निविदाओं में पारदर्शिता एवं सुगमता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली निविदाओं के लिये राज्य में वर्ष –2006 से ई– टेण्डरिंग प्रणाली संचालित है। शासन के सभी विभाग/संस्थाओं के लिए e-procurement portal का संचालन किया जा रहा है। विभाग की सभी निविदाएँ ऑनलाइन की जाती है। इस प्रणाली से पिछले वित्त वर्ष मे 61 हजार करोड़ रूपये मूल्य की 54 हजार 847 निविदाएँ जारी की गयी है। ईएमडी एवं निविदा प्रपत्र बिक्री का भुगतान ई–पेमेंट द्वारा किया जाता है।

एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क –

राज्य में वर्तमान 21 हजार 553 एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से राज्य शासन के विभिन्न विभाग द्वारा प्रदान की जा रही 450 शासकीय सेवाए पारदर्शी तरीके से सुविधाजनक रूप से नागरिकों को उनके निकटतम स्थान पर ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जा रही है।

आई.टी/ई गवर्नेंस प्रशिक्षण –

राज्य शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों को ई– गवर्नेंस एवं आई.टी. परियोजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति सुग्राही करने तथा उनमे कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौघोगिकी संबंधी अन्य उपकरणों के उपयोग के लिए आवश्यक दक्षताओं के संवर्धन के लिये प्रदेश के सभी 51 जिले मे ई. दक्ष केन्द्र स्थापित किये गये है। प्रत्येक केन्द्र से दो दो प्रशिक्षक की जिला ई– गवर्नेंस सोसायटी द्वारा नियुक्ति की गई है। इस साल सितम्बर तक लगभग 85 हजार अधिकारी कर्मचारियों को आई.टी/ गर्वनेंस से संबधित प्रशिक्षण दिया गया। मंत्रालय स्थित कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र में प्रारंभ से इस साल सितम्बर तक 4000 अधिकारी–कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

वर्चुअल क्लॉस–रूम –

वर्चुअल क्लास–रूम परियोजना में प्रदेश के उत्कृष्ट विषय–विशेषज्ञों द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेसिंग सुविधा द्वारा 413 केन्द्र में शिक्षण जारी है। परियोजना के प्रारंभ से इस साल सितम्बर तक लगभग दो हजार व्याख्यान का प्रसारण कर 40 लाख से अधिक विघार्थी का लाभान्वित किया जा चुका है।

जीआईएस/एम.पी.एस.एस.डी.आई –

प्रदेश के नक्शों का एकीकृत डेटाबेस तैयार कर GIS के माध्यम से निर्णय सहायक तंत्र का विकास करना है। मध्यप्रदेश स्टेट स्पेशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर नीति में प्रदेश के सभी विभाग को जी आई एस की प्रारंभिक क सुविधाएं देने के लिए परियोजना क्रियान्वित की गयी।

जी आई एस के लिए आवश्यक सेटेलाइट इमेज को सभी उपयोगकर्ताओं को साझा किया जाकर शासन को 23 करोड़ से अधिक की वचत गत एक वर्ष मे हुई। प्रदेश के सभी विभाग के जी आई एस डाटा की Single repository तैयार किये जाने का कार्य चल रहा है।[6]

प्रदेश के खसरा नक्शों का एकीकृत जीआईएस डाटा का निर्माण 94 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष ग्रामों के जीआई एस नक्शें तैयार करने की कार्यवाही जारी है। उपलब्ध नगरीय एवं वन सीमा के नक्शों का

संधारण का कार्यपूर्ण हो चुका है। शेष नगरीय निकाय के जीआईएस नक्शे तैयार किये जा रहे है। अब तक बन स्कूल, शिक्षा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जीआईएस डाटा को Single respoitory में संधारित किया जा चुका है। संधारित डाटा को उपयोगकर्ताओं से साझा करने के लिए वेब सर्विसेस का विकास कर उक्त पोर्टल मे उपलब्ध करवाया जा चुका है। इन बेब सर्विसेस के माध्यम से उपयोगकर्ता मेप आई टी मे संधारित डाटा को अपने विभागीय वेब अथवा डेस्टकॉप आधारित एप्लीकेशन में सबसे उपयोग कर सकेंगे। एमपीएसएसडीआई परियोजना मे कई विभाग/संस्था परियोजना जैसे राज्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा ट्राईफेक जलसंसाधन पुरात्त्व, पर्यटन आदि लाभान्वित हुए है।

एम.पी मोबाइल –

एम.पी. मोबाइल प्लेटफार्म के माध्यम से 154 नागरिक केन्द्रित सेवाओं का प्रदाय किया जा रहा है।

कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा –

राज्य शासन के विभिन्न विभागों, कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, संस्थाओं आई. टी. ऑपरेटर सहायक ग्रेड3 शीघ्रलेखक स्टेनो टायपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य लिपिकीय स्तर के पदों पर संविदार्थियों के चयन के लिये कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा करवायी जाती है। कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण की 9 अक्टूबर 2016 तक 7 परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई जिनमें 24 हजार 262 अभ्यार्थी शामिल हुए इस तरह से भारतीय प्रतिभा को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़कर बेहतर भारत का निर्माण करने के उद्देश्य से भारत सरकार डिजीटल इण्डिया कार्यक्रम प्रदेश में संचालित है। कार्यक्रम मे प्रदेश की सक्रिय भागीदारी के लिए कार्य प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगी डिजिटल अधोसंरचना की उपलब्धता करवाना और नागरिकों का डिजीटल सशक्तिकरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किया जा रहा है।[7]

बैगलुरू को एशिया की सिलिकॉन बैली माना जाता है, लेकिन अब मध्यप्रदेश आईटी स्टेट बन गया है। आज मध्यप्रदेश में अधिकांश लेनदेन केशलेस हो रहा है। मध्यप्रदेश कैशलेस लेन–देन के मामले में अन्य राज्यो के लिए रोल मॉडल बन गया है।

डिजीटल मध्यप्रदेश बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैः–

- ❖ प्रदेश मे पी. ओ. एस. मशीने वेट और प्रवेश कर से मुक्त।
- ❖ प्रधानमंत्रीा जनधन योजना में 2 करोड़ 29 लाख बैंक खते खोले गये।
- ❖ एक करोड़ 67 लाख रूपें कार्ड जारी।
- ❖ प्रदेश के 11 हजार 864 ग्रामीण सब सर्विस एरिया में ''बैंक सखी'' और बैंक मित्र'' के माध्यम से भुगतान प्राप्ति की व्यवस्था।
- ❖ समस्त स्कॉलरशिप का ऑनलाइन वितरण।
- ❖ एम.पी. मोबाइल एप द्वारा 150 से अधिक नागरिक सेवायें।
- ❖ कोषालयो द्वारा समस्त भुगतान ऑनलाइन
- ❖ ई– सम्पदा– एक क्लिक पर संपत्ति का पंजीयन
- ❖ ई–मेल नीति जारी करने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य/ऑफिशियल ई– मेल पर किये गये संवाद वैधानिक।
- ❖ डिजिटल जातिप्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था
- ❖ शासकीय योजनाओं के सभी हितग्राहियों का सीधे बैंक खाते में राशि भुगतान की व्यवस्था।
- ❖ नागरिक सुविधाऐं ऑनलाइन देने की व्यवस्था।
- ❖ नागरिक सुविधा केन्द्र के रूप में 23 हजार एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क 14 हजार कॉमन सर्विस सेन्टर और 413 लोक सेवा केन्द्र संचालित। मध्यप्रदेश की मंडियों में 95 प्रतिशत लेन–देन केस लेस में हो रहा है। राशि सीधे किसानों के खाते मे हस्तांतरित हो जाती हैं। सहकारिता विभाग म.प्र. शासन द्वारा

सहकारी क्षेत्रा के पहले बॉलेट 'सहकार बटुआ' का शुभारंभ किया गया है। सरकार द्वारा निरन्तर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और देवास में भी डिजी–धन मेले निरन्तर लगाये जा रहे हैं।

REFERENCES (निष्कर्ष) –

म.प्र. में कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा विकसित किए जा रहे एक नवीन साफ्टवेयर आईएफएमआईएस से अब शासकीय कार्यालय के सभी लेन–देन कार्य ऑनलाइन होगें। शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेख, जी पीएफ, डी,पी एफ, बी.एफ अवकाश, नगदीकरण, वेतन, भत्ते पेंशन आदि कार्य ऑनलाइन स्वीकृत होगे।[7] सभी विभाग मई पेड इन जून 2017 का वेतन नवीन साफ्टवेयर आईएफएम आई एस से आहरित करेगें इसके संचालन के लिए कोषालय द्वारा लोग–इन पासवर्ड तैयार कर डी डी ओ, एडमिन एच ओओ एडमिन, एवं पे–रोल एडमिन, रोल बनाया जा चुका है। लॉग इन पासवर्ड के जरिये शासकीय सेवक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही अपने सेवा अभिलेख देख सकेगें। इस तरह मध्यप्रदेश को एक नई दिशा देने का प्रयास ऑनलाइन संस्कृति को राजव्यवस्था का अंग बनाकर करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को ई–गवनर्स के माध्यम से त्वरित सेवाएँ मिल सके।

References (संदर्भ) –

1. अशोक कुमार दुबे, 21 वी शताब्दी में लोक प्रशासन टाटा मेग्रा हिल्स, नई दिल्ली पृष्ठ 188
2. रचना सुचिन्मयी समसामयिक राजनीतिक मुद्धे रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृष्ठ 303
3. बालेन्दु शर्मा, कुरूक्षेत्रा, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्राालय, भारत सरकार नई दिल्ली पृष्ठ 26–27
4. राजेश पाण्डेय, आलेख, आई.टी. अधोसंरचना विकास के कार्य जारी, http:/mpinfo.org: से उद्धरित पृष्ठ 1–4
5. http://mpinfo.org/story/story/
6. रोजगार और निर्माण, संपादक पुष्पेन्द्र पाल सिंह, म. प्र. माध्यम द्वारा प्रकाशित दिनांक 26/12/2017 पृष्ठ 5
7. म.प्र. माध्यमः द्वारा प्रकाशित, रोजगार और निर्माण भोपाल म.प्र. दिनांक

सूची

आधार ग्रन्थ

1. **मोरवाल भगवानदास, 'काला पहाड़', राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999**
2. **मोरवाल भगवानदास, 'बाबल तेरा देस में', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004**
3. **मोरवाल भगवानदास, 'अस्सी मॉडल उर्फ सूबेदार', प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1997**
4. **मोरवाल भगवानदास, 'लक्ष्मण रेखा', सनफ्लावर बुक्स, नई दिल्ली, 2010**

सहायक ग्रन्थ

1. **चौहान वी.पी, 'रामदरश मिश्र के कथा साहित्य में ग्राम्य जीवन', चिन्तन प्रकाशन, कानपुर, 2004**
2. **दूबे श्यामचरण, 'भारतीय समाज', नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 1985**

अंग्रेजी पुस्तक सूची

1. **Maciver R.M., Page C.H., 'Society: An Introductory Analysis', Macmilan Company, London, 1962.**
2. **Wright, 'Elements of Sociology' University of London Press, 1942**

डॉ. दीपक कुमार मोदी
(अतिथि शिक्षक) , राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग ,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)